(c) what is the quantum of power expected to be generated through private sector by giving such incentives ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA-KUMAR) : (a) and (b) For attracting private sector investment to promote new & renewable sources of energy, the financial and fiscal incentives, such as soft term loans, accelerated depreciation allowance, excise duty & central sales tax exemptions, concessional customs duty, general sales tax exemption/deferrment, tax holiday for 5 years and capital subsidy are already being provided by the Government. Many of the State Government are also providing facilities of wheeling, banking, third party sale and buy-back of power generated by private enterpreneurs.

(c) During the 8th Plan period 500 to 1000 MW of power generation capacity is expected to be set up through private participation using the financial and fiscal incentives announced by the Central as well as State Governments.

सूक्ष्म लघु जल विद्युत परियोजना

2051. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किन्ही वित्तीय संस्थाओं से सूक्ष्म/लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कोई वित्तीय सहायता अथवा ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या है तथा प्रत्येक संस्था से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और इसमें से मध्य प्रदेश राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान सूक्ष्म/लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को कितनी धन राशि उपलब्ध कराई गयी है ; और

(घ) क्या उपलब्ध कराई गई धनराशि पर्याप्त है ?

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इरेडा को 15 मेवा० स्टेशन क्षमता तक सिचाई बांध तलहटी और नहर प्रपात आधारित लघु विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से 70.00 मिलियन अमरीकी डालर ऋण उपलब्ध हो गया है । निजी उद्यमियों और विभिन्न राज्यों के सरकारी क्षेत्र के संगठनों को समग्र दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण उपलब्ध है जो गुण पर आधारित होता है । राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य सरकारों के विभाग ऋण के लिए पात्र नहीं है और राज्य-वार नियतन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को छः चालू लघु विद्युत परियोजनाओं के लिए 340.00 लाख रुपये का आवंटन किया है । इस आवंटन की पर्याप्तता चालू परियोजनाओं की प्रगति और नई परियोजनाओं की जरूरतों पर निर्भर करेगी।

Wind Energy Projects in Gujarat

2052. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the number of wind-energy projects being operated in Gujarat and the capacity of each of the project, location-wise ;

(b) the expenditure incurred on each of the projects ;

(c) whether all the plants are working as per their installed capacity ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the steps taken by Government to make them fully operational ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE. (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) and (b) The details of